बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 86 ● नई दिल्ली ● सोमवार 12 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल से फरार रेप का आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल ने यौन शोषण के मामले में पाँच साल से फरार चल रहे आरोपी सुमित मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ 2021 में पश्चिमी दिल्ली के रनहेला थाना में रेप और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था लेकिन तभी से वह पुलिस की पकड़ से बाहर था. कोर्ट ने उसी साल उसे भगोड़ा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर दिया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने 7 मार्च 2021 को पुलिस में शिकायत दी थी कि वह सिविल डिफेंस की नौकरी के लिए फॉर्म भरवाने आरोपी की दुकान पर गई थी. वहीं से आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और बाद में दस्तावेज देने के बहाने संपर्क में आया. आरोप है कि इसी दौरान उसने युवती का यौन शोषण किया और उसे गर्भवती भी कर दिया.

एनसीएपी अब नाममात्र का स्वच्छ वायु कार्यक्रम बनकर रह गया है : जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि वायु गुणवत्ता एक राष्ट्रव्यापी, संरचनात्मक संकट है जिसके लिए सरकार की प्रतिक्रिया अत्यंत अप्रभावी और अपर्याप्त है। विपक्षी दल ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में व्यापक सुधार की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार जिस एनसीएपी को 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) बताकर प्रचारित कर रही है, वह असल में एनसीएपी का ही एक और रूप यानी नोशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) द्वारा किए गए एक नए विश्लेषण ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत का सबसे खराब छिपा हुआ रहस्य यह है कि वायु गुणवत्ता एक राष्ट्रव्यापी, संरचनात्मक संकट है जिसके लिए सरकार की प्रतिक्रिया बेहद अप्रभावी और अपर्याप्त है। रमेश ने एक बयान में कहा कि उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए किए गए अध्ययन में पाया गया कि भारत के लगभग 44 प्रतिशत शहरों, यानी आकलन वाले 4,041 वैधानिक शहरों में से 1,787 शहर लगातार वायु प्रदूषण की गंभीर चपेट में हैं और इन शहरों में पांच वर्षों (2019-2024, 2020 को छोड़कर) के दौरान हवा में वार्षिक पीएम 2.5 का स्तर लगातार राष्ट्रीय मानकों के ऊपर बना रहा है।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की अक्षमता को भी उजागर किया है। उनके मुताबिक, समस्या के विशाल पैमाने (1787 शहर) के बावजूद एनसीएपी के तहत केवल 130 शहरों को शामिल किया गया।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इन 130 शहरों में से 28 शहरों में अब भी निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) मौजूद नहीं हैं। रमेश ने बताया कि निगरानी अवसंरचना वाले 102 शहरों में से 100 शहरों में पीएम10 का स्तर 80 प्रतिशत या उससे अधिक पाया गया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, एनसीएपी वर्तमान में भारत के गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों में से केवल चार प्रतिशत शहरों को कवर करता है। उन्होंने कहा कि जिस एनसीएपी को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, वह वास्तव में एक अलग ही किस्म का एनसीएपी बन गया- 'नोशनल स्वच्छ वायु कार्यक्रम। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब इसकी गहन समीक्षा, व्यापक सुधार और पुनर्गठन की सख्त जरूरत है। रमेश ने कहा, पहला कदम भारत के बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को स्वीकार करना होना चाहिए। परिणामस्वरूप, इस संकट को देखते हुए, हमें वायु प्रदूषण (नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम 1981 और नवंबर 2009 में लागू किए गए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस), दोनों की फिर से समीक्षा करनी चाहिए और उनमें पूर्णतः संशोधन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय मानकों (एनएएक्यूएस) के अनुसार हवा में अतिसूक्ष्म कणों की स्वीकार्य मात्रा 24 घंटे में 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और सालाना 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक यह मात्रा 24 घंटे में 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम और साल भर में पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम होनी चाहिए। रमेश ने सरकार से एनसीएपी के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले कोष में भारी वृद्धि करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, एनसीएपी की धनराशि और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों को मिलाकर मौजूदा बजट लगभग 10,500 करोड़ रुपये है, जो 131 शहरों में वितरित किया गया है। हमारे शहरों को कम से कम 10-20 गुना अधिक धनराशि की आवश्यकता है। एनसीएपी को 25,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और इसे देश के 1,000 सबसे प्रदूषित शहरों/कस्बों में वितरित किया जाना चाहिए। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने कहा कि एनसीएपी को अपने प्रदर्शन का पैमाना पीएम 2.5 के स्तर को बनाना चाहिए और एनसीएपी को अपना ध्यान प्रमुख प्रदूषण स्रोतों पर केंद्रित करना चाहिए जैसे ठोस ईंधनों का जलाना, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक उत्सर्जन। उन्होंने तर्क दिया, एनसीएपी को कानूनी आधार दिया जाना चाहिए, उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था होनी चाहिए, और केवल 'नॉन अटेनमेंट शहरों तक सीमित रहने के बजाय देश के हर शहर के लिए गंभीर और सशक्त डेटा निगरानी क्षमता विकसित की जानी चाहिए। रमेश ने जोर देकर कहा कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए वायु प्रदूषण मानदंडों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक संसद में दो बार- पहली दफा 29 जुलाई 2024 को और दूसरी बार नौ दिसंबर 2025 को- मोदी सरकार ने वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कमतर दिखाने की कोशिश की है। मोदी सरकार सच में अनजान नहीं है, बल्कि वह अपनी अक्षमताओं और लापरवाही के पैमाने को छिपाने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली में जाली दस्तावेजों से लोन धोखाधड़ी करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वाहन लोन लेने के लिए जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर बैंक लोन धोखाधड़ी में शामिल एक संगठित सिंडिकेट के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने धोखे से लोन लिया और बेईमानी की नीयत से वाहन खरीदकर उन्हें बेच दिए। आरोपितों ने वाहन लोन लेने के लिए पहले अलग-अलग नामों से जाली आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाया फिर उन्हीं नामों से आइटीआर भरने के भी जाली दस्तावेज बनवाए और जाली दस्तावेज के आधार पर पांच वाहन खरीद कर बेच दिए। इनके कब्जे से फिलहाल पांच वाहन मर्सिडीज, ब्रेज़ा, अल्ट्रोज़, स्कार्पियो-एन और टोयोटा हिलक्स बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के मुताबिक एसीपी अनिल शर्मा, इंस्पेक्टर संदीप सिंह व विनय कुमार की टीम को 25 दिसंबर को जाली दस्तावेज का इस्तेमाल कर वाहन लोन लेने में शामिल एक संगठित सिंडिकेट के बारे में जानकारी मिली। जांच में पता चला कि लोन मिलने के बाद, आरोपितों ने जानबूझकर रीपेमेंट में डिफाल्ट किया। ट्रैकिंग से बचने के लिए वाहनों को अलग-अलग राज्यों में री-रजिस्टर कराया गया। अमन कुमार नाम के शख्स ने राहुल कपूर, श्याम सुंदर, राय कपूर आदि नामों से जाली दस्तावेज बनाकर उनके नाम पर बैंक खाते खोले और वाहन लोन लिए। आधार और पैन कार्ड की जांच से सही पहचान की पुष्टि हुई, क्योंकि कई पहचानों में तस्वीरें आरोपित से मेल खाती थीं। जांच के बाद अमन कुमार के घर पर छापा मारा गया, जिससे जाली दस्तावेज और वाहन से संबंधित रिकार्ड बरामद हुए। यह साबित हुआ कि उसने धोखे से वाहन लोन लिया, वाहन खरीदे और बेईमानी की नीयत से उन्हें बेच दिया। जिसके बाद क्राइम ब्रांच में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। जांच के बाद बीते शुक्रवार को अमन उर्फ श्याम सुंदर उर्फ राहुल कपूर को तिलक नगर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह पहचान छिपाने के लिए कई नकली नाम, पहचान और पते इस्तेमाल कर रहा था। जानबूझकर पेमेंट न करने के कारण बाद में इन लोन को नान-परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) घोषित कर दिया गया। लोन पर वाहन खरीदने के बाद, उसने उन्हें अलग-अलग लोगों को बेच दिया। उससे पूछताछ के बाद दूसरे आरोपित धीरज, नजफगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में पता चला कि वह अमन के साथ मिलकर कई नकली पहचान, जैसे आलोक और सिद्धार्थ, का इस्तेमाल करके जाली पैन कार्ड, आधार कार्ड और जाली आइटीआर का इस्तेमाल करके बैंक खाते खोले थे। इन खातों का इस्तेमाल वाहन लोन लेने के लिए किया गया था, जिनका बाद में जानबूझकर पेमेंट नहीं किया गया। बाद में वाहनों को अलग-अलग लोगों को बेच दिया गया।

जांच में धीरज ने बताया कि जाली आधार कार्ड साई दस्तावेज सेंटर में बनाए जाते थे। टीम ने दुकान का दौरा कर मालिक से पूछताछ कर नरेश कुमार, नजफगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।

अमन की निशानदेही पर तीन गाड़ियां टाटा अल्ट्रोज़, मारुति ब्रेज़ा व मर्सिडीज-बेंज मिली। धीरज से भी दो गाड़ियां स्कार्पियो-एन व टोयोटा हिलक्स बरामद की गई। नरेश के पास से एक मोबाइल फोन, आई स्कैनर, बायोमेट्रिक स्कैनर, वेब कैमरा, पीवीसी कार्ड मशीन बरामद की गई।

टैक्स सुधार और मिडिल क्लास की उम्मीदों क़ा निर्णायक पड़ाव

वैश्विक स्तरपर भारत का आम बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह देश की आर्थिक सोच सामाजिक प्राथमिकताओं और वैश्विक भूमिका को परिभाषित करने वाला नीति-घोषणापत्र होता है। वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट इस दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत करेगा, बल्कि भारत के आयकर ढांचे में होने वाले सबसे बड़े कानूनी परिवर्तन से पहले का अंतिम पूर्ण बजट भी होगा। यही कारण है कि संसद से लेकर शेयर बाजार तक, टैक्सपेयर्स से लेकर उद्योग जगत तक और भारत से लेकर वैश्विक निवेशकों तक,सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैंमैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र बता दूं कि वर्ष 2026- 27 के बजट का औपचारिक आगाज़ संसद के बजट सत्र के साथ होगा, जिसे 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक आयोजित करने की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दी जा चुकी है। यह सत्र दो चरणों में विभाजित होगा, पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा।इसविस्तारित सत्र का उद्देश्य केवल बजट पारित करना नहीं, बल्कि उससे जुड़ी नीतियों, संशोधनों और विधायी पहलुओं पर व्यापक विमर्श सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र में बजट सत्र सरकार और संसद दोनों के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी होता है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। यह क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनका एक और बजट होगा, जिसमें उनसे न केवल राजकोषीय अनुशासन बल्कि मिडिल क्लास, नौकरीपेशा वर्ग, किसानों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के बीच संतुलन साधने की अपेक्षा की जा रही है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में बजट के हर प्रावधान का सीधा असर घरेलू मांग, निवेश वातावरण और वैश्विक भरोसे पर पड़ता है। साथियों बात अगर हम टैक्सपेयर्स की उम्मीदें- बजट का सबसे संवेदनशील पक्ष इसको समझने की करें तो,हर बजट में अगर किसी एक वर्ग की निगाहें सबसे अधिक वित्तमंत्री के भाषण पर टिकी होती हैं, तो वह है टैक्सपेयर्स विशेषकर मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोग। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रिटायरमेंट की बढ़ती लागत के बीच यह वर्ग वर्षों से यह महसूस करता आया है कि आर्थिक विकास का सबसे बड़ा बोझ उसी के कंधों पर है। इसलिए बजट 2026-27 में इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं केवल वित्तीय नहीं,बल्कि सामाजिकराजनीतिक संदेश भी होंगी। साथियों बात अगर हमस्टॉक मार्केट की तैयारी- बजट और निवेशकों का संबंध इसको समझने की करें तो बजट 2026- 27 का असर केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव शेयर बाजार और पूंजी बाजार पर भी पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंजों ने संकेत दे दिए हैं कि यदि 1 फरवरी को बजट रविवार के दिन पेश किया जाता है,तो उस दिन स्पेशल ट्रेडिंग सेशनआयोजित किया जाएगा। यह व्यवस्था दर्शाती है कि बजट घोषणाओं को बाजार कितनी गंभीरता से लेता है। टैक्स सुधार, पूंजीगत लाभ कर, टीडीएस नियम और निवेश प्रोत्साहन जैसे प्रावधान बाजार की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथियों बात अगर हम नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक युग का अंत, दूसरे की शुरुआत को समझने की करें तो, यूनियन बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बनाने वाला सबसे बड़ा कारण यह है कि यह 60 साल पुराने आयकर कानून के अंत से पहले का अंतिम पूर्ण बजट होगा। सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है, जो मौजूदा जटिल विवादग्रस्त और बार-बार संशोधित कानून की जगह लेगा। ऐसे में बजट 2026-27 केवल मौजूदा वित्तीय जरूरतों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले टैक्स सिस्टम की बुनियाद भी रखेगा।

साथियों बात अगर हम टैक्सपेयर्स की 5 बड़ी उम्मीदें- क्या मिडिल क्लास की खुलेगी किस्मत? इसको समझने की करें तो(1)धारा 80सी और 80डी की सीमा में वृद्धि -बचत और सुरक्षा का सवाल-धारा 80सी के तहत ?1.5 लाख की कर छूट सीमा वर्षों से अपरिवर्तित है,जबकि इस अवधि में महंगाई, आय स्तर और जीवन-शैली खर्चों में भारी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली छूट भी आज की चिकित्सा लागत के मुकाबले अपर्याप्त प्रतीत होती है। टैक्सपेयर्स की प्रमुख मांग है कि इन सीमाओं को यथार्थवादी स्तर तक बढ़ाया जाए, ताकि लंबी अवधि की बचत, बीमा कवरेज और सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहन मिल सके।(2)लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में राहतनिवेशसंस्कृति को बढ़ावा-भारत सरकार निवेश आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स की मौजूदा संरचना कई निवेशकों को हतोत्साहित करती है। टैक्सपेयर्स की अपेक्षा है कि या तो इसकी आय सीमा बढ़ाई जाए, या फिर छोटे और मध्यम निवेशकों को अतिरिक्त राहत दी जाएइससे घरेलू निवेश, रिटेल पार्टिसिपेशन और पूंजी बाजार की गहराई बढ़ सकती है, जो वैश्विक निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत होगा।(3) टीडीएस सीमा में वृद्धिनकदी प्रवाह और अनुपालन की सरलता- टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) व्यवस्था का उद्देश्य टैक्स संग्रह को आसान बनाना है, लेकिन अत्यधिक कम सीमाएं कई बार अनावश्यक अनुपालन बोझ पैदा करती हैंवरिष्ठ नागरिकों, फ्रीलांसर्स और छोटे करदाताओं की मांग है कि विभिन्न श्रेणियों में टीडीएस की सीमा बढ़ाई जाए, जिससे नकदी प्रवाह सुधरे और रिफंड- आधारित टैक्स सिस्टम पर निर्भरता कम हो।(4)नए इनकम टैक्स कानून में सरल संरचना - जटिलता से मुक्ति-इनकम टैक्स एक्ट 2025 से सबसेबड़ी उम्मीद यह है कि यह सरल, स्पष्ट और विवाद-मुक्त होगा। बजट 2026-27 में सरकार से अपेक्षा है कि वह इस नए कानून की संरचना को स्पष्ट संकेतों के माध्यम से पेश करे जैसे कम धाराएं,सरल भाषा, डिजिटल- फ्रेंडली अनुपालन और न्यूनतम व्याख्यात्मक विवाद। यह सुधार भारत की ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और वैश्विक टैक्स छवि को भी मजबूत करेगा। (5) विवाद समाधान और टैक्स आतंक से मुक्ति-पिछले वर्षों में सरकार ने 'टैक्स टेररिज़्म' की धारणा को समाप्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी लंबे विवाद, अपीलें और मुकदमेबाजी टैक्सपेयर्स के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। बजट 2026-27 से अपेक्षा है कि इसमें तेज, पारदर्शी और तकनीक-आधारित विवाद समाधान तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। साथियों बात अगर हम इस बजट को दो एंगल मिडिल क्लास व शेयर बाजार केंद्रित से समझने की करें तो (1) मिडिल क्लास केंद्रित आय, बचत और जीवन- स्तर की कसौटी-बजट 2026- 27 मिडिल क्लास के लिए इसलिए निर्णायक है क्योंकि यह नए इनकम टैक्स कानून से पहले का अंतिम पूर्ण बजट हैनौकरी पेशा और मध्यम आय वर्ग की प्रमुख अपेक्षा यह है कि बढ़ती महंगाई, शिक्षा-स्वास्थ्य खर्च और रिटायरमेंट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स ढांचे में वास्तविक राहत दी जाए। विशेष रूप से धारा 80सी और 80डी की सीमाओं में वृद्धि मिडिल क्लास के लिए केवल टैक्स लाभ नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का साधन मानी जा रही हैयदि बजट में कर-छूट या टैक्स स्लैब में संतुलित सुधार होता है, तो इसका सीधा असर घरेलू खपत पर पड़ेगा। ऑटो, आवास, उपभोक्ता वस्तुएँ और सेवाएँ,ये सभी सेक्टर मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम से चलते हैं। इसलिए, बजट 2026-27मिडिल क्लास के लिए इस प्रश्न का उत्तर देगा कि क्या सरकार उसे केवल टैक्स बेस के रूप में देखती है या आर्थिक विकास का इंजन मानती है।(2) शेयर बाजार केंद्रित-भरोसा,स्थिरता और दीर्घकालिकसंकेत-शेयर बाजार के लिए बजट 2026-27 अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से अधिक नीतिगत दिशा और टैक्स स्थिरता का दस्तावेज है।निवेशकों की प्राथमिक अपेक्षा यह है कि कैपिटल गेन टैक्स, टीडीएस और कॉरपोरेट टैक्स से जुड़े संकेत स्पष्ट और पूर्वानुमेय हों। टैक्स अनिश्चितता बाजार को कमजोर करती है,जबकि स्थिरता दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करती है। यदि बजट में राजकोषीय अनुशासन के साथ कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को प्राथमिकता दी जाती है।

सम्पादकीय...

नयी शिक्षाएं बताने से हमें हर्गिज इंकार नहीं

दुनिया वालो, अब तो तुम्हें झख मारकर मानना पड़ेगा कि मोदी जी का भारत ही विश्व गुरु है! और किसी के विश्व गुरु होने का तो पहले भी कोई चांस नहीं था। कोई वास्तविक कंपटीशन तो कभी था ही नहीं। और अब, जो नयी-नयी शिक्षाएं भारत दुनिया के सामने हर रोज पेश कर रहा है, उसके बाद मोदी जी के भारत के सामने कोई और विश्व गुरु बन जाए, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। हां! फिर भी अगर दुनिया बाकायदा मोदी जी को विश्व गुरु का आसन नहीं देती है, तो अपना ही नुकसान करेगी। मोदी जी का तो क्या जाता है, ये दुनिया वाले ही निगुरे रह जाएंगे। और निगुरे रह गए तो अज्ञानी तो अपने आप रह ही जाएंगे। हमारे संतों ने तो पहले ही चेता दिया था—बिन गुरु ज्ञान कहां से पावे! अब प्लीज यह बचकानी मांग कोई न करे कि ये नयी-नयी शिक्षाएं क्या है, जिन्होंने विश्व गुरु के आसन पर मोदी जी के भारत का दावा एकदम मोहर लगाकर पक्का कर दिया है। नयी शिक्षाएं बताने से हमें हर्गिज इंकार नहीं है। कोई पूछेगा तो हम जरूर बताएंगे और छाती ठोककर बताएंगे। चीज ही बताने वाली है। बचकानी मांग सिर्फ इसलिए कहा कि नयी शिक्षाएं क्या है, कोई अगर उनका बखान करना भी चाहे तो कर नहीं सकता है। शिक्षाएं हैं ही इतनी सारी कि उनका पूरा बखान असंभव है। हरि अनंत है, सो उसकी कथा भी अनंत होगी ही। खैर! दुनिया वालों के लिए पेश करते हैं, नमूने की दो-तीन नयी शिक्षाएं कि सारी दुनिया देखे और सीखे। और मोदी जी के भारत की उदारता देखिए, कोई फीस नहीं लगायी है, न देखने पर और न सीखने पर! पहले, सब का साथ सब का विकास की सीख। जम्मू-कश्मीर नाम के प्रदेश में, जब सारे विभाजन पट गए और लोहे के खंभों से प्रदेश को सीधे मोदी जी की राजगद्दी के साथ बांध दिया गया, तब जो विकास की सुनामी आयी, उसमें जम्मू के वैष्णो देवी ट्रस्ट के हिस्से में एक यूनिवर्सिटी आ गयी और यूनिवर्सिटी के हिस्से में पचास सीटों का एक मेडिकल कालेज आ गया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चल भी पड़ा। मेडिकल कालेज का पहला साल ठीक-ठाक गुजर भी गया। पर जब दूसरे साल के एडमिशन का समय आया और नीट की अखिल भारतीय परीक्षा में मैरिट के आधार पर दाखिले के योग्य पाए गए छात्रों की सूची आयी, तो वैसे भी हमेशा खतरे में रहने वाला सनातन एकदम खतरे में पड़ गया। पचास में से कुल 7 उम्मीदवार हिंदू, जबकि 42 मुसलमान और एक सिख। सत्य सनातन का अपमान अब क्यों सहेगा भारत महान! मोदी जी की पार्टी समेत, उनके विचार परिवार के तमाम संगठन आंदोलित हो उठे। विचार परिवार आंदोलित हुआ, तो मीडिया आंदोलित हुआ। मीडिया भी आंदोलित हुआ, तो सरकार विचलित हुई। डबल इंजन वाली सिचुएशन नहीं थी, सो पहले एलजी विचलित हुआ। एलजी विचलित हुआ तो उसका कंपन दिल्ली के तख्त तक पहुंचा। पर एक समस्या थी। विचार परिवार की बोली में दिल्ली की सरकार कैसे कहे कि जिस कॉलेज के नाम में वैष्णो देवी लगा है, उसमें मुसलमान ज्यादा भर्ती नहीं हो सकते। यह तो एडमीशन जिहाद हो जाएगा। तब विश्व गुरु ने अपना कटोरा दांव लगाया। दिल्ली ने इशारा किया और मेडीकल कालेज ही वर्तमान से भूतपूर्व हो गया। जब बांस ही नहीं रहा, तो बांसुरी कैसे बजती। न सरकार ने एडमीशन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, न मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ और सनातनियों का जीत का जश्न भी मन गया। माता वैष्णो देवी के नाम की पवित्रता की रक्षा भी हो गयी और सर्वधर्म समभाव को कोई शिकायत करने का भी मौका नहीं मिला। और यह सब सिर्फ एक मेडिकल कालेज की छोटी सी कुर्बानी से! है और कोई दुनिया को ऐसी अद्भुत सीख देने वाला! उसके बाद, ज्ञान-विज्ञान को हमेशा आगे रखने की सीख। मध्य प्रदेश में जबलपुर में नानाजी देशमुख के नाम से एक वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी खुली। नानाजी संघ विचार परिवार के तो यूनिवर्सिटी का ज्ञान-विज्ञान भी विचार परिवार का। उस पर गोरक्षा से प्राचीन संस्कृति तथा परंपरा तक की रक्षा का जोश। सनातनी वैज्ञानिकों ने शोध की एकदम नयी दिशा में क्रांतिकारी कदम बढ़ा दिए। गाय के गोबर और गोमूत्र से कैंसर की दवा बनाने का शोध। शोध के मैदान में विचार परिवार का पहलवान, तो विचार परिवार की सरकार मेहरबान। गोबर और गोमूत्र से कैंसर की दवा के शोध के लिए साढ़े तीन करोड़ रु0 का फंड मिल गया। शोध के क्रम में जहां पौने दो करोड़ रु0 गोबर और गोमूत्र पर खर्च किए गए, वहीं करीब पचीस लाख गाड़ी की खरीद पर और बाकी डेढ़ करोड़, गोवा के दौरों पर। शोधकर्ताओं ने गोवा के 23-24 दौरे किए। आखिर, गोवा के नाम में भी तो गो आता ही है। इस कनेक्शन पर गहन शोध जरूरी था, सो हुआ। क्या हुआ कि कैंसर की दवा नहीं बन पायी, पर गोबर, गोमूत्र के साथ गोवा का कनेक्शन तो पूरी तरह से साबित हो गया। है दुनिया में कोई और जो ऐसे-ऐसे मोर्चों पर विज्ञान को आगे रखने की प्रेरणा दे सकता हो? और हर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बनाने की सीख! नमस्ते ट्रंप का इवेंट किया, मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप-2.0 के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया, वह भी मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप ने बार-बार, बार-बार, व्यापार की धमकी दिखा कर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का दावा किया और मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, मास्टर स्ट्रोक। बाद में विदेश मंत्रालय के मंझले अधिकारियों से खंडन कराया, वह भी मास्टर स्ट्रोक। यह प्रचार कराया कि मोदी जी ट्रंप का फोन उठा ही नहीं रहे, मास्टर स्ट्रोक। अब ट्रेड डील अपनी अकड़ से बिगड़वाने के इल्जाम के जवाब में, ट्रंप को आठ बार फोन करने का ब्यौरा दे रहे हैं, वह भी मास्टर स्ट्रोक। गज़ा पर इस्राइल की तरफ दारी, मास्टर स्ट्रोक। वेनेजुएला पर चुप, वह भी मास्टर स्ट्रोक। कहां मिलेगा कोई और ऐसा, मास्टर आफ मास्टर स्ट्रोक! अंत में सिर्फ एक चिंता! इससे पहले कि ट्रंप का ध्यान विश्व शांति नोबेल से हटकर, विश्व गुरु के आसन की ओर खिंच आए, मोदी जी को जल्दी से भारत के लिए विश्व गुरु का आसन पक्का करा लेना चाहिए। वर्ना कहीं ऐसा न हो कि ट्रंप विश्व गुरु की दावेदारी की लाइन में भी लग जाए और शांति के नोबेल की तरह, भारत को विश्व गुरु की लाइन से भी बाहर होना पड़ जाए। आखिर, पाकिस्तान के साथ लड़ाई यकायक रोकने के लिए, शांति का नोबेल तो हमारा भी बनता ही था।

बंगाल से भेदभाव का आरोप

पश्चिम बंगाल में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी के साथ जो टकराव देखने को मिला वह स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में पहली बार देखने को मिला। ईडी जैसी केन्द्रीय जांच एजेंसी के आई पैक पर छापे के दौरान ममता बनर्जी के वहां पहुंचने और आई पैक के सह संस्थापक के दफ्तर से हरे रंग की फाइल और हार्ड डिस्क उठाकर चल देने की घटना अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस टकराव से ममता बनर्जी की स्ट्रीट फाइटर के रूप में वापसी हो चुकी है। शायद तृणमूल कांग्रेस को ईडी के साथ टकराव में राजनीति लाभ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी ममता बनर्जी को जोरदार तरीके से निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं और उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने जो किया वह दंडनीय अपराध है। आई पैक पर छापे के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर मामला अदालत तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है तो दूसरी तरफ ईडी ने भी अदालत में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दी है। अब फैसला अदालत ही करेगी। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति का अतीत देखें तो ममता बनर्जी शुरू से ही सड़क की राजनीति करती आई हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी नेतृत्व है। वह सत्ता में रहते हुए भी आम लोगों के बीच रही हैं। धरना, पद यात्रा और सड़क पर उतर कर विरोध करना उनकी राजनीतिक शैली का अहम हिस्सा रहा है। व्यक्तिगत जीवन में ममता बनर्जी सादगी की मिसाल हैं। साधारण साड़ी, चप्पल और बेहद सामान्य रहन-सहन उनके व्यक्तित्व को अन्य नेताओं से अलग बनाता है। सत्ता और वैभव से दूर रहकर जनता के बीच रहने का अंदाज उन्हें खास बनाता है। ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर चोटें खाईं और अपने सहयोगियों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसके चलते वो एक के बाद एक सफलताएं अर्जित करती गईं। मां माटी और मानुष के नारे पर राजनीति करने वाली ममता बनर्जी का जुझारूपन लोगों को काफी आकर्षक लगा। बंगाल में दीदी कही जाने वाली ममता बनर्जी ऐसी नेता बनीं जिसने भारत की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों लेफ्ट, कांग्रेस और भाजपा को हराकर जीत हासिल की। ममता ने इसकी शुरुआत लेफ्ट पार्टी से की और उन्होंने 1984 में लोकसभा चुनावों में दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। पश्चिम बंगाल में दशकों से चले आ रहे वामपंथी शासन को उखाड़ फैंकने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर में ऐसी सड़क की राजनीति की जिसके बल पर खुद को गरीबों की आवाज बताने का दावा करने वाले वामपंथी शासन को 2011 में सत्ता से उखाड़ दिया। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के दौरान राज्य का औद्योगिक विकास रुक गया था। ज्योति बसु के जाने के बाद मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भट्टाचार्य ने औद्योगिक विकास शुरू करने के लिए इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को निवेश के लिए बुलाया। टाटा को नैनो कार प्रोजेक्ट के लिए बुलाया, पर जनता से जमीन लेने की कोशिश डंडे के दम पर की गई। मुआवजा भी बराबर नहीं मिल रहा था। इसको लेकर जनता सड़क पर आ गई थी। वामपंथी सरकार ने दमन का सहारा लिया। धीरे-धीरे किसानों का आंदोलन राज्यव्यापी होता गया। नंदीग्राम, सिंगूर में धरना-प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया। गोलियां चलीं, हिंसा हुई। एक नाबालिग तापसी मलिक का रेप और हत्या हो गई।

ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को युद्ध बना दिया और 26 दिन तक आमरण अनशन पर बैठी रहीं। इस आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र भी सामने आया। वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने विरोधियों की लगातार हत्याएं कीं। आंदोलन सफल रहा और लेफ्ट की सरकार एक भी इंडस्ट्रीयल नहीं ला सकी। टाटा अपना कारोबार समेट कर गुजरात के सानंद में चले गए। तब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही थे। लेफ्ट के पांव तले की जमीन खिसक गई और उसे सत्ता गंवानी पड़ी। लेफ्ट को हराने के एक दशक बाद ममता बनर्जी ने एक टांग के सहारे भाजपा को हराया। वह भी तब जब भाजपा किसी भी क्षेत्रीय नेता के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनावों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के लिए चुनौती बनकर उभरी है। ममता बनर्जी की सरकार में घोटालों की एक लम्बी लिस्ट भी दिखाई देती है। सारदा चिटफंड घोटाला, पीजी स्कीम घोटाला। नारदा स्टिंग कोयला तस्करी, राशन वितरण घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला आदि में पार्टी के कई मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इन गिरफ्तारियों को ममता बनर्जी हमेशा बदले की कार्रवाई बताती रहीं और केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाती रहीं। कई बार सीबीआई, ईडी जैसी केन्द्रीय एजेंसियां बंगाल पुलिस के बीच टकराव भी हुआ। टकराव तो राजभवन से भी खूब हुआ। फिर चाहे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी रहे हों, जगदीप धनखड़ रहे हों या फिर सीवी आनंद बोस। ममता बनर्जी केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाती हैं। उज्ज्वला, पीएम आवास और मनरेगा जैसी केंद्र की तमाम योजनाओं के लिए फंड रोकने का आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि मोदी-शाह किसी भी तरह से बंगाल को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। वहीं, दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी, ममता बनर्जी का चित्रण एक तानाशाह की तरह करती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में आक्रामक चुनाव अभियान चलाया। टीएमसी के दिग्गज नेता और ममता बनर्जी के बेहद खास रहे सुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर सुवेंदु ने ममता बनर्जी को चुनौती दी और उन्हें हरा भी दिया। हालांकि, अपनी नेता की हार के बावजूद टीएमसी ने 2021 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 213 सीटों पर जीत दर्ज की।

'रील्स के दुरुपयोग'

आज की तारीख में सोशल मीडिया भारत के लिए एक बुरी खबर ला रहा है। नैतिकता और संस्कार खत्म हो रहे हैं। हमारा युवा वर्ग किधर जा रहा है, इसे फोकस में रख कर कुछ करने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में 'रील्स' मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स पर 15 से 60 सैकंड के ये वीडियो आज हर उम्र के व्यक्ति की पहली पसंद बन चुके हैं लेकिन मनोरंजन के नाम पर शुरू हुआ यह सिलसिला अब धीरे-धीरे 'रील्स के दुरुपयोग' और एक गंभीर सामाजिक लत में बदलता जा रहा है। किसी भी रील के जरिए झूठ फैला कर दंगे कराने जैसी घिनौनी साजिशें इसी रील के माध्यम से की जा रही हैं। सरकार को कुछ करना ही होगा। रील्स ने सूचना और मनोरंजन के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है लेकिन इसके पीछे एक काला सच भी छिपा है। आज रील्स केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहीं, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक मूल्यों और शारीरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन गई है। मेरा यह मानना है कि माता-पिता को अपने बच्चों को घरों में उनकी मोबाइल से जुड़ी गतिविधियों को लेकर नजर रखनी चाहिए। इतना ही नहीं जब वे देर रात तक घर नहीं आते या रात को घर में ही रहने पर मोबाइल में रीलें एक-दूसरे से शेयर करते रहते हैं तो इस पर भी माता-पिता को नजर रखनी होगी। रील्स के चंगुल में फंसा हर व्यक्ति एक के बाद एक वीडियो देखता जाता है जिससे मस्तिष्क में डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। यह ठीक वैसी ही लत है जैसी शराब या जुए की होती है। अब कुछ करना ही होगा। लोग दूसरों की रील्स में दिखाई गई चमक-धमक वाली जिंदगी से अपनी वास्तविकता की तुलना करने लगते हैं जो कि डिप्रेशन वाली है। लगातार छोटे वीडियो देखने से इंसानी दिमाग की एकाग्रता कम हो रही है। अब लोग लंबी फिल्में या किताबें पढ़ने में असमर्थ महसूस करते हैं। मीडिया की सुर्खियां बता रही हैं कि आजकल वायरल होने की चाहत में लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाना, चलती गाड़ी की छत पर स्टंट करना या ऊंची इमारतों से लटकना-ये सब रील्स के दुरुपयोग के खतरनाक उदाहरण हैं। कई बार इन स्टंट्स के चक्कर में युवाओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। प्रेस के लिए मीडिया रेगुलेटरी है तो रील्स पर कंट्रोल के लिए भी सरकार को कुछ रेगुलेटरी लानी होगी। प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया ने मीडिया जगत में अपनी एक गौरवपूर्ण पहचान बनाई है। मैंने पाया है कि व्यूज और फॉलोअर्स बटोरने के लिए कई लोग रील्स पर अश्लील डांस, अभद्र भाषा और द्विअर्थी संवादों का सहारा ले रहे हैं। चूंकि ये वीडियो हर उम्र के बच्चों तक पहुंच रहे हैं, इसलिए यह उनके कोमल मन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। लिहाजा अब सरकार से अनुरोध है कि वह इस दिशा में कुछ करने के लिए पग उठाए। किसी बड़े स्टार की मौत पर उसकी पत्नी के साथ किसी अन्य कलाकार के अश्लील कंटेंट डालने को क्या कहेंगे? कहीं भी बुलडोजर चलने को किसी जाति के साथ जोड़कर चलने का काम रील द्वारा किया जा रहा है। साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कुछ रेगुलेटरी तो लानी ही होगी। रील बनाने में युवा पैसे कमाने के लिए अपना असली मकसद भुलाकर दिशा से भटक चुका है।

मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जश्न मना, महाराष्ट्र में सभी पार्टियां बेनक़ाब

यह सही है कि इंडिया' ब्लॉक का गठन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था और उसके बाद इसकी प्रासंगिकता ज्यादा नहीं है। राज्यों में विपक्षी पार्टियों को इस गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन चुनावी राजनीति से अलग जिस तरह से संसद सत्र के दौरान इस गठबंधन की पार्टियां मिल कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती है वैसी कोई पहल संसद के बाहर नहीं दिखती है। इसकी मिसाल मनरेगा बचाओ आंदोलन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अकेले चल रही है। कांग्रेस ने किसी अन्य विपक्षी पार्टी के संपर्क नहीं किया है। 10 जनवरी से उसका देश भर में अभियान शुरू हो गया है। कांग्रेस की कई सहयोगी पार्टियों ने कहा कि अगर उनसे संपर्क किया जाता है तो वे इस आंदोलन में शामिल हो सकते थे। चुनावी राज्यों में खास कर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता था। मगर कांग्रेस अकेले यह लड़ाई लड़ना चाहती है। इसमें मुश्किल यह है कि कांग्रेस के पास अनेक राज्यों में बहुत मजबूत संगठन नहीं है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में कांग्रेस सिर्फ विरोध की औपचारिकता निभा रही है। बिहार और झारखंड में तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही इतने कमजोर हैं कि उनके कहने से कहीं 10 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। गौरतलब है कि इन राज्यों में मनरेगा के लाभार्थियों की बड़ी संख्या है। अगर समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी पार्टियां भी साथ होतीं तो कांग्रेस इसे बड़ा आंदोलन बना सकती थी।

मेडिकल कॉलेज बंद होने पर जश्न मना

देश में अस्पतालों, डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों की कितनी कमी है, इसका अंदाजा देश भर में बने सरकारी अस्पतालों के बाहर सड़कों और फुटपाथों पर डेरा जमाए बीमार लोगों और उनके परिजनों को देख कर लगाया जा सकता है। इसीलिए आमतौर पर होता यह है कि लोग अपने शहर या जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं और जब उनकी मांग पूरी हो जाती है तो वे ढोल-धमाके के साथ अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर में इसका ठीक उलटा हुआ है। वहां लोगों ने मेडिकल कॉलेज बंद कराने के लिए संघर्ष किया और जब उनकी मांग पूरी हो गई तो उन्होंने जमकर खुशी मनाई। जम्मू स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता भारत सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसलिए रद्द कर दी, क्योंकि 50 सीटों वाले उस कॉलेज में मैरिट के आधार 42 मुस्लिम छात्रों को दाखिला मिला था। दाखिला पाने वाले आठ अन्य छात्रों में सात हिंदू और एक सिख था। ये सभी 50 छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा (एनईईटी) में सफल होकर आए थे। जम्मू के हिंदू संगठनों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि वैष्णो देवी के चढ़ावे से चलने वाले मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीटों पर मुसलमान कैसे आ सकते हैं? बस इसी बात को लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज बंद करने की मांग की और उनकी मांग पर सरकार ने तकनीकी कमियों का बहाना बनाते हुए मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी।

इस बार बजट रविवार को पेश होगा

इस बार आम बजट रविवार को पेश हो सकता है। केंद्र सरकार की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हर साल की तरह इस साल भी 28 जनवरी से बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की है। साल के पहले संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है और उसके बाद वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है और फिर एक फरवरी को बजट पेश होता है। इस बार एक फरवरी रविवार को है। इसीलिए यह संशय पहले से जताया जा रहा है कि रविवार को कैसे बजट पेश होगा। लेकिन जानकार बताते हैं कि सरकार का इसमें बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। अगर सरकार बजट पेश करने की तारीख में बदलाव नहीं करती है तो रविवार को भी संसद की कार्यवाही चलेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कहा जा रहा है कि वित्तीय प्रक्रियाओं का चक्र और उनकी स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार रविवार को ही बजट पेश करेगी। गौरतलब है कि पहले 28 फरवरी को बजट पेश होता था। लेकिन 2017 में सरकार ने कहा कि 28 फरवरी को बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को एक अप्रैल से लागू करने में समस्या आती है। इसलिए 2017 से एक फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा।

रेखा गुप्ता का इतिहास ज्ञान

सोशल मीडिया में इस बात पर हैरानी है कि किसी मुख्यमंत्री का इतना स्लिप ऑफ टंग' कैसे हो सकता है, जितना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हो रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि रेखा गुप्ता ने इस देश के दो सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीदे आजम भगत सिंह के बारे में गलतबयानी की और उसके बाद भाजपा के लोग जुबान फिसल जाने का तर्क लेकर आए। इसीलिए सवाल है कि क्या हर बार उनकी जबान फिसल रही है या वे इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं जानती हैं? दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रेखा गुप्ता ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को याद किया और कहा कि कांग्रेस की बहरी सरकार को सुनाने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। इसे जुबान फिसलना कहेंगे या अज्ञान? ऐसा लग रहा है कि वे नहीं जानती हैं कि भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और अंग्रेजों ने ही उन्हें फांसी दी थी। इसी तरह कुछ दिन पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया तो नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस बोल गईं। नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस पीतमपुरा में एक मार्केट प्लेस है। वैसे इतिहास का अटपटा ज्ञान बघारने वाली रेखा गुप्ता भाजपा की अकेली मुख्यमंत्री नहीं हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अपने ऐसे ही अटपटे बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं।

महाराष्ट्र में सभी पार्टियां बेनक़ाब

वैसे तो पूरे देश में ही राजनीतिक दलों का एकमात्र मकसद सत्ता प्राप्त करना होता है लेकिन महाराष्ट्र का मामला उसमें भी सबसे अलग है। वहां नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में सभी पार्टियों का एक दूसरे के साथ गठबंधन था। इस सिलसिले में अब जो खबर आई है वह सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। दो नगर परिषदों पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने एक जगह कांग्रेस से और दूसरी जगह दूसरी जगह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम से हाथ मिला लिया। पहला मामला ठाणे की अंबरनाथ नगर परिषद का है, जहां 60 में से 27 सीटें भाजपा की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिव सेना ने जीती है। लेकिन अपनी सहयोगी पार्टी को रोकने के लिए भाजपा ने कांग्रेस से तालमेल कर लिया।

भाजपा के 14 और कांग्रेस के 12 सदस्य जीते है। इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी के चार सदस्यों को साथ जोड़ लिया गया। ऐसे ही अकोला जिले की अकोट नगर परिषद पर कब्जे के लिए भाजपा ने अकोट विकास मंच बना लिया, जिसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों की शिव सेना और शरद व अजित पवार दोनों की एनसीपी शामिल है। ओवैसी की पार्टी के चार सदस्य भी इसी से जुड़े है। जब इस बात के लिए आलोचना शुरू हुई तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने गठबंधन तोड़ने की बात कही तो कांग्रेस ने अपने सदस्यों को निलंबित कर दिया। कहा जा रहा है कि यह फैसला स्थानीय स्तर पर किया गया था। लेकिन यह लोगों की आंखों में धूल झोंकना है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

वैश्य महासंघ द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में सामाजिक एकता और समरसता पर दिया गया विशेष जोर

मेजा, प्रयागराज।

भारतीय राष्ट्रीय वैश्य महासंघ के तत्वावधान में रविवार को क्षेत्र के अमिलहवा स्थित स्वयंवर गेस्ट हाउस में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामाजिक समरसता भोज कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ-साथ सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा देना रहा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम के आयोजक दुर्गा प्रसाद गुप्ता रहे, जबकि आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी डॉ. सुखलाल साहू ने निभाई। समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद उजवल रमण सिंह रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन हरिओम साहू ने दीप प्रवलित कर किया, वहीं अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेजा जंगी लाल गुप्ता ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रकांता साहू, जितेंद्र गुप्ता, राजेश परदेसी साहू एवं कृष्ण कुमार साहू मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में मुकेश कुमार साहू, प्रदीप सांवरा एवं डॉ. नीता साहू ने अपने विचार रखे।समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद उजवल रमण सिंह ने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान किसी भी समाज की उन्नति का मजबूत आधार होता है। इससे न केवल प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि समाज में सकारात्मक वातावरण भी बनता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक

समरसता और आपसी सहयोग के बिना समृद्ध समाज की कल्पना संभव नहीं है। सभी वर्गों को मिल-जुलकर शिक्षा, सेवा और विकास के कार्यों में भागीदारी निभानी चाहिए।उद्घाटनकर्ता हरिओम साहू ने कहा कि वैश्य समाज ने देश और समाज के विकास में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में सामाजिक समरसता की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और आपसी मतभेद भुलाकर समाजहित में कार्य करने पर जोर दिया। आयोजक दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य समाज की उन प्रतिभाओं को सम्मानित करना है, जिन्होंने शिक्षा, समाजसेवा, व्यापार, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनुभवी चिकित्सकों द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा जरूरतमंदों को मुफ्त दवाइयों का वितरण किया गया।

उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय वैश्य महासंघ भविष्य में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम के संरक्षक रामपति एवं तेज बहादुर गुप्ता रहे। संयोजक मंडल में ओम चंद गुप्ता, कृष्ण मणि गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, मौजी लाल गुप्ता, मुरारी गुप्ता, संतोष गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, राजूराम गुप्ता, अंजनी कुमार गुप्ता, जटाशंकर गुप्ता (प्रधान), रवि गुप्ता, पत्रकार सतीश चंद्र गुप्ता, रवि शंकर गुप्ता, रमेश चंद्र गुप्ता एवं नंदलाल गुप्ता सहित अनेक लोग शामिल रहे।समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में आयोजित सामाजिक समरसता भोज में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। पूरे कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एकता, सौहार्द और भाईचारे का संदेश स्पष्ट रूप से देखने को मिला।

बाबू शरीफुद्दीन पाशा की याद में किए गए कंबल वितरण

सपा विधायक हाजी मौहम्मद फहीम इरफान ने महिलाओं को किए कंबल वितरित

बिलारी।

नगर के अंबेडकर पार्क में ठंड व शीतलहर से बचाव के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन आईटीएम ट्रस्ट कुन्दरकी के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने करीब 160 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने कहा कि ठंड के इस मौसम में जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा मानव धर्म है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल सभी के जीवन में सुख, शांति और तरक्की लेकर आए। इस दौरान विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने अपने संबोधन में कहा कि यह सेवा कार्य उनके ससुर स्वर्गीय बाबू शरीफुद्दीन पाशा की स्मृति और उनके सेवा भाव से प्रेरित होकर किया जा रहा है, जिन्होंने हर वर्ष बिलारी में आकर नव वर्ष के मौके पर कम्बल वितरण करते थे, जिन्होंने जीवनभर समाज के कमजोर वर्गों की मदद को प्राथमिकता दी। कार्यक्रम में ट्रस्ट परिवार के सदस्य आरिफ पाशा, आसिफ पाशा, बेटी शहनाज परवीन एवं सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने जरूरतमंद वृद्ध व विधवा महिलाओं को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम में शेरपुर माफी, असालतपुर, मुड़िया भीकम, मिलक नागलिया जट, टांडा अमरपुर, मनकुला, सतारन, विचोला कुंदरकी, इशापुर, मीरापुर माफी, धनिया खेड़ा सहित कई गांवों के जरूरतमंद मौजूद रहे। इस अवसर पर सद्दाम सैफी ग्राम प्रधान, हप्पू राजा सभासद, कुर्बान प्रधान, बाकार युनुस प्रधान, पूर्व प्रधान रियाज अहमद, अरविंद सिंह, छत्रपाल जाटव, डा0 कुंवर सिंह जाटव, केके नवल, रामवीर सिंह, बादाम सिंह जाटव, विजयपाल सिंह जाटव, सूरज सिंह जाटव, प्रेमकिशोर, जसवंत सिंह डा0 विजयदीप, अतर सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

मुसाँस की मनोरंजक सभा में हुआ प्रतिभागियों का सम्मान

मुरादाबाद।

महानगर की प्रतिष्ठित संस्था मुसाँस-मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज द्वारा आज लोहड़ी एवं मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में खिचड़ी पार्टी के रूप में एक मनोरंजक पिकनिक सभा का आयोजन बुद्धि विहार में किया गया। कार्यक्रमोपरांत नगर के सबसे सुंदर पार्क संविधान साहित्य वाटिका का भ्रमण भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल, संस्थापक अध्यक्ष दीपक बाबू सीए, अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, सचिव डॉ0 पंकज दर्पण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष ममता गर्ग ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। संयोजक सुषमा गर्ग द्वारा अनेक मनोरंजक खेल कराये।

विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ. पंकज दर्पण अग्रवाल ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए महापौर विनोद अग्रवाल ने मुसाँस के क्रिया कलापों की प्रशंसा करते हुए संस्था को अपनी ओर से हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया। महापौर द्वारा राखी अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अलका विश्नोई और अजय विश्नोई का सम्मान किया। ममता गर्ग, मनवी कोठीवाल, साधना अग्रवाल, अजीत अग्रवाल, राजेश सिंघानिया, स्वाति कोठीवाल, अनुराधा गुप्ता, हिमांशु गर्ग, राजू खन्ना, सीए मनु मेहरोत्रा, अरविंद गुप्ता, डॉ. संतोष मेहरोत्रा, सुषमा रस्तोगी, रूही रस्तोगी, कर्नल अतुल भटनागर, रवि प्रकाश अग्रवाल, रेनु सक्सेना, तनु मेहरोत्रा, सोनम मेहरोत्रा, शुभम बंसल, वंदना कपूर, अदिति अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, चित्रा अग्रवाल, नमिता अग्रवाल, जे के गोयल, विकास सक्सेना, अनिता मदान, विपिन जैन आदि का सक्रिय सहयोग रहा।

वार्डन्स को बचाव विधियों का कराया अभ्यास

मुरादाबाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशालय नागरिक सुरक्षा उ0 प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार एमआईटी संस्थान के सभागार में वार्डन एवं स्वयंसेवक के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सत्र के छठ्ठम दिन प्रशिक्षण सत्र में सर्वप्रथम इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना की गई । तत्पश्चात आर के शर्मा, डिप्टी सीएमे ओ द्वारा पहले सेशन में मानव शरीर की संरचना आदि के बारे में बताया गया। साथ ही डॉ शर्मा द्वारा सीपीआर आदि बचाव विधियों का अभ्यास भी कराया गया। दूसरे सेशन में डॉ अनुपमा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा सामूहिक दुर्घटना के मामले में ट्राईएज पर चर्चा की गई जिसमें व्यक्ति के रोल पर विस्तृत चर्चा कर दायित्वों को समझाया गया। छठे दिन के अंतिम सेशन में सतीश कुमार सहायक उपनियंत्रक प्राथमिक उपचारकर्ता के कर्तव्य आदि को समझाया गया। सभी वक्ताओं/व्याख्यान विशेषज्ञों का स्वागत उपनियंत्रक नीरज चक द्वारा पुष्पगुंछ से किया गया। कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा कार्यालय से तुषार अग्रवाल डिविजन वार्डन मो खालिद, डिप्टी डिविजन वार्डन विचित्र शर्मा, विचित्र शर्मा, स्टाफ अधिकारी वसीम अंसारी, वसीम अख्तर, शफीक अहमद घटना नियंत्रण अधिकारी अनुज गुप्ता आदि ने उपस्थित रह कर सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में अशोक कुमार गुप्ता, शरीफा अहमद एडवोकेट का भी विशेष सहयोग रहा।

सम्मेलन में मनरेगा मजदूरों के हक में बुलंद की आवाज़

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन का 15 वाँ राज्य सम्मेलन रविवार को क्लासिक बैंकट हाल में आरंभ हुआ। सर्वप्रथम यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने संगठन का झंडा फहरा कर शहीदों को याद किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव बी0 वैंकेट ने कहा कि खेत एवं ग्रामीण मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी मजदूरी कम हो रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, साथ ही उनके लिए लम्बे संघर्षों से से हासिल किये गए कानूनों और सुविधाओं पर हमला हो रहा है।

केन्द्र सरकार ने मनरेगा को खतम करके काम की गारंटी खतम कर दी है और रोजगार को अधिकार की बजाय सरकार की इच्छा के आधीन कर दिया है। श्रमिक संहिताएँ लागू कर के 8 घंटे काम का अधिकार छीन लिया है। प्राथमिक विद्यालय बंद करके सरकार गरीब बच्चों, खासतौर पर बाँचयों की शिक्षा छीन रही है। संगठन के सह सचिव विक्रम सिंह ने कहा कि संविधान देश के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है पर सरकारी संरक्षण में हिंदुत्ववादी ताकतें महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही हैं। उन्होंने कहा की खेत मजदूर यूनियन लोगों की रोज़ी रोटी पर हमले और धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र, समानता और सांविधान पर हमले के दोहरे खतरे के खिलाफ मेहनतकशों को एकजुट करेगी। यूनियन के महासचिव बी0एल0 भारतीय ने कहा कि आने वाले समय में यूनियन गाँव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चलायेगी। उन्होंने 12 फरवरी को मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में थान सिंह, राजनाथ, पूनम यादव आदि ने भी सम्बोधित किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्ष की यात्रा पर हुआ विराट हिन्दू सम्मेलन

कसानगंज । नगर पंचायत कसानगंज प्राचीन गौशाला ठाकुर जी के मंदिर प्रांगण परिसर में रविवार को पर दिनांक 11 जनवरी 2026 दिन रविवार को प्रातः 11:00 बजे से विराट हिन्दू सम्मेलन 2 बजे प्रारंभ हुआ जो शाम तक चला। तदोउपरांत शोभायात्रा निकाली गई जो गौशाला प्रांगण से आजाद चौक चांदनी चौक मंगल की बाजार धर्मशाला रोड होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर संपन्न हुआ। जिसमें नगर के तथा आसपास के अपार हिंदू जनमानस माताएं बहने तथा भाइयों की उपस्थिति रही प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक श्री सूर्य प्रभात जी मुख्य वक्ता की भूमिका में रहे तथा संत समाज से धर्म जागरण के जिला परियोजना प्रमुख आचार्य श्री सतीश चतुर्वेदी जी तथा मातृशक्ति से बहन श्रृंखला किशोरी द्विवेदी जी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। तथा अध्यक्ष की भूमिका में श्री गंगासागर की उपस्थित सभी सम्मिलित रहे हिंदू जनमानस के प्रति आभार तथा धन्यवाद ज्ञापित किये।

मकर संक्रांति पर डीडीए का बड़ा तोहफा, राजधानी में 582 फ्लैट्स ई-ऑक्शन के लिए तैयार

नई दिल्ली। दिल्ली में अपना घर लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए नया साल अच्छी खबर लेकर आ रहा है. मकर संक्रांति के मौके पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी बहुप्रतीक्षित प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 लॉन्च करने जा रहा है. इस योजना के तहत दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में बने फ्लैट्स और पार्किंग स्पेस ई-ऑक्शन के जरिए खरीदे जा सकेंगे. डीडीए की कोशिश है कि अलग-अलग आय वर्ग के लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकें. डीडीए की इस नई स्कीम में कुल 582 प्रॉपर्टीज को शामिल किया गया है. इनमें HIG, MIG, LIG, जनता और EHS कैटेगरी के फ्लैट्स के साथ-साथ कार और स्कूटर गैराज भी मौजूद हैं. खास बात यह है कि फ्लैट्स दिल्ली के प्रीमियम और रिहायशी इलाकों में हैं, जिससे लोगों को लोकेशन को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाई इनकम ग्रुप यानी HIG फ्लैट्स की बात करें तो जसोला में सबसे ज्यादा फ्लैट्स रखे गए हैं. यहां 15 HIG फ्लैट्स उपलब्ध होंगे, जिनका रिजर्व प्राइस करीब 2.14 करोड़ रुपये तय किया गया है. वहीं सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के फ्लैट्स रोहिणी, वसंत कुंज, गाजीपुर और द्वारका जैसे इलाकों में मिलेंगे. इनकी कीमत लगभग 99 लाख से लेकर 1.21 करोड़ रुपये तक रखी गई है. मिडिल इनकम ग्रुप के खरीदारों के लिए भी डीडीए ने कई विकल्प दिए हैं. दिलशाद गार्डन, द्वारका, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, जहांगीरपुरी, लोकनायकपुरम, मादीपुर, नंदनगरी और रोहिणी में MIG फ्लैट्स शामिल किए गए हैं. इन फ्लैट्स का रिजर्व प्राइस 53 लाख रुपये से शुरू होकर करीब 1.45 करोड़ रुपये तक जाता है. लो इनकम ग्रुप यानी LIG फ्लैट्स करोल बाग, द्वारका, रोहिणी, विकासपुरी, पश्चिम विहार और अन्य इलाकों में उपलब्ध होंगे. इनकी कीमत 20 लाख से लेकर 1.23 करोड़ रुपये तक तय की गई है. शाहपुर जट में एक जनता फ्लैट रखा गया है, जिसका रिजर्व प्राइस लगभग 18 लाख रुपये है. वहीं HIG कैटेगरी के फ्लैट्स द्वारका, अशोक नगर, कोंडली और नसीरपुर में मिलेंगे, जिनकी कीमत 26 लाख से 55 लाख रुपये के बीच होगी. इस स्कीम में सिर्फ फ्लैट्स ही नहीं, बल्कि पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है. अशोक विहार, माल रोड, रोहिणी और पीतमपुरा में कार और स्कूटर गैराज उपलब्ध होंगे. इनका रिजर्व प्राइस 3 लाख रुपये से लेकर 42 लाख रुपये तक रखा गया है. ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा करना जरूरी होगा. LIG, EHS और जनता फ्लैट्स के लिए 4 लाख रुपये, MIG और स्मार फ्लैट्स के लिए 10 लाख रुपये और HIG फ्लैट्स के लिए 15 लाख रुपये तय किए गए हैं. कार गैराज के लिए 4 लाख और स्कूटर गैराज के लिए 1 लाख रुपये अर्नेस्ट मनी रखी गई है. रजिस्ट्रेशन और अर्नेस्ट मनी जमा करने की प्रक्रिया 14 जनवरी सुबह 11 बजे से शुरू होगी. आवेदन की आखिरी तारीख 13 फरवरी है, जबकि फाइनल सबमिशन 16 फरवरी तक किया जा सकेगा. ई-ऑक्शन का शेड्यूल 19 फरवरी को जारी होगा और 20 से 22 फरवरी तक डेमो रखा जाएगा.

वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन: पीएम मोदी बोले- भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, पूरी दुनिया की बढ़ीं उम्मीदें

राजकोट।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन से पहले राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में एक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिन के गुजरात दौरे पर है। 10 जनवरी को पीएम मोदी सीधे सोमनाथ पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने राजकोट में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है और देश आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी ने कहा, 2026 के आरंभ के बाद ये मेरा गुजरात का पहला दौरा है और सुखद इसलिए भी है क्योंकि 2026 की मेरी यात्रा सोमनाथ दादा के चरणों में सिर झुकाकर शुरू हुई है और अब मैं राजकोट में इस शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं यानी विकास भी विरासत भी, ये मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। बीते वर्षों में भारत ने बहुत तेज प्रगति भी की है और इसमें गुजरात की, आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है और देश आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में महंगाई नियंत्रण में है और कृषि उत्पादन नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत आज दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर वन है, वहीं जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन निर्माण में भी भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता बन गया है। PI आज दुनिया का नंबर-1 रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एविएशन सेक्टर में भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, जबकि मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के मामले में भी भारत दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा, सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात के ऐसे इलाके हैं जो हमें सिखाते हैं कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी और कड़ी मेहनत से लगे रहें, तो सफलता जरूर मिलती है। यह वही कच्छ है जिसने इस सदी की शुरुआत में एक विनाशकारी भूकंप का सामना किया था। यह वही सौराष्ट्र है जहां वर्षों तक सूखा पड़ना आम बात थी। महिलाओं और लड़कियों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। बिजली का कोई भरोसेमंद इंतजाम नहीं था...समय बदलता है, और यह सच में बदलता है। सौराष्ट्र और कच्छ के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दी है।

आज, सौराष्ट्र और कच्छ सिर्फ मौकों के इलाके नहीं हैं, बल्कि वे भारत की तरक्की के लिए एक मजबूत आधार बन गए हैं। पीएम मोदी बोले, सौराष्ट्र और कच्छ भारत के हरित विकास, हरित गतिशीलता और ऊर्जा सुरक्षा का भी एक बड़ा हब बन रहा है। कच्छ में 30 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पार्क पेरिस शहर से भी पांच गुना बड़ा है। यानी इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता के साथ-साथ व्यावसायिक पैमाने की वास्तविकता भी है। आप सभी हरित हाइड्रोजन की क्षमता से परिचित हैं। भारत में इस दिशा में अभूतपूर्व गति और पैमाने पर काम चल रहा है। यहां कच्छ और जामनगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बड़े केंद्र बन रहे हैं। कच्छ में एक विशाल बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर क्षेत्र में नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म। जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जेनरेशन जसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा... रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा सुधार इन्श्योरेन्स सेक्टर में किया है... इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों करदाताओं को फायदा हुआ है। भारत ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म को भी लागू कर दिया है... यानी श्रमिक हो या फिर इंडस्ट्री सभी का इससे फायदा है।

पीएम मोदी ने की निवेश की अपील

पीएम मोदी कहते हैं, मैं यह बात लंबे समय से कह रहा हूं, अगर आप इसमें देरी करेंगे तो मुझे दोष मत देना। सौराष्ट्र-कच्छ में आपका हर निवेश गुजरात और देश के विकास में योगदान देगा। अभी रवांडा की हाई कमिश्नर बता रही थी कि जब वह रवांडा गई, तो उन्होंने वहां 200 गायें गिफ्ट की थीं। ये 200 गायें हमारी गिर गायें थीं।

जब हम वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 200 गायें देते हैं, तो एक नियम है कि पहला बछड़ा हमें वापस करना होगा। हम उन्हें दूसरे परिवारों को दे देते हैं। यानी, वह 200 गायों से शुरू हुआ था। वे गायें हजारों परिवारों तक पहुंच गई हैं। यह रवांडा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ताकत दे रहा है। सबरीमाला में सोना नहीं बचा पाए तो धर्म क्या बचाएंगे, अमित शाह ने साधा केरल सरकार पर निशाना

हिजाब पर फिर गरमाई सियासत, पीएम पद को लेकर हिमंत बिस्वा-ओवैसी में तीखी जंग

नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ओवैसी ने इच्छा जताई कि वे एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।

ओवैसी ने क्या कहा था?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में केवल एक खास धर्म के व्यक्ति को ही पीएम बनने की अनुमति है, लेकिन बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान भारत के हर नागरिक को यह मौका देता है।

उन्होंने कहा, मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने।

हिमंत बिस्वा सरमा का जवाब

ओवैसी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के सीएम ने कहा कि भले ही संविधान किसी को भी पीएम बनने से नहीं रोकता, लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही बनेगा।

ओवैसी का पलटवार

रविवार को ओवैसी ने सीएम सरमा के बयान को छोटी सोच वाला बताया और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ओवैसी ने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पीएम केवल हिंदू ही हो सकता है।

कांग्रेस ने भी सरमा की आलोचना की

इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरमा की आलोचना की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि वे एक सिख थे और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मसूद ने कहा कि संवैधानिक पदों पर कौन बैठेगा, यह धर्म तय नहीं कर सकता।

बीजेपी ने ओवैसी को घेरा

बीजेपी के अन्य नेताओं ने ओवैसी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि ओवैसी जानबूझकर हिजाब का मुद्दा उठाकर तनाव बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने तर्क दिया कि दुनिया भर में कई मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनी हैं, लेकिन उन्होंने हिजाब नहीं पहना। उन्होंने ओवैसी को चुनौती दी कि वे पहले अपनी पार्टी में किसी हिजाब पहनने वाली महिला को बड़े पद पर आगे बढ़ाएं।

सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमटे- पीएम मोदी

***गजनी से औरंगजेब तक सब नष्ट हो गए, सोमनाथ मंदिर आज भी अडिग खड़ा है - पीएम मोदी**

***दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद- प्रधानमंत्री मोदी**

गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोमनाथ मंदिर में आयोजित भव्य स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान सोमनाथ की पूजा-अर्चना की और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। यह अवसर इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह महमूद गजनवी द्वारा मंदिर पर किए गए पहले हमले (साल 1026) के 1,000 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सोमनाथ का इतिहास केवल विनाश का नहीं, बल्कि हर बार गिरकर फिर से खड़े होने और विजय का इतिहास है। उन्होंने कहा कि आज सोमनाथ के मंदिर पर लहराता ध्वज पूरी दुनिया को भारत की शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दे रहा है।

1,000 साल का संघर्ष

पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि एक हजार साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी आस्था और महादेव के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने कहा, जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम हमलावर सोमनाथ को नष्ट कर रहे थे, तो उन्हें लगा था कि उनकी तलवारें सनातन को जीत लेंगी।लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि सोमनाथ का अर्थ ही अमृत है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि आज जहाँ हमले के 1,000 साल हो रहे हैं, वहीं मंदिर के आधुनिक पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों और गुलामी की मानसिकता रखने वाले लोगों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी कुछ लोगों ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, तो उन्हें भी बाधाओं का सामना करना पड़ा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कि 1951 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद मंदिर आए थे, तब भी उन पर आपत्तियां जताई गई थीं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा भारत की सांस्कृतिक विरासत को दबाने की कोशिश की। इस उत्सव की भव्यता का वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1,000 ड्रोन द्वारा दिखाई गई सोमनाथ की गाथा, 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा और 72 घंटों तक लगातार चलता मंत्रोच्चार मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहा। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल बीते हुए समय का स्मरण नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व और अभिमान का उत्सव है।

हरियाणा में पीएम मोदी की अगुवाई में अभूतपूर्व विकास कार्य लगातार जारी : सीएम नायब सैनी

इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अभूतपूर्व विकास कार्य लगातार जारी हैं और हमारी सरकार बेटियों के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

कुरुक्षेत्र। लाड़वा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अभूतपूर्व विकास कार्य लगातार जारी है और हमारी सरकार बेटियों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। महिलाओं को 2100 वित्तीय आर्थिक सहायता दे रहे हैं। अब तक हम 280 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दे चुके हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि माता बहनों को रसोई में 500 में गैस सिलेंडर देंगे और आज यह गैस सिलेंडर हरियाणा प्रदेश के कई माता बहनों के घर पहुंच रहा है। आज पंजाब की भूमि माछीवाड़ा साहिब में मुझे नमन करने का अवसर मिला जो ऐतिहासिक भूमि है। आज पंजाब की भूमि पर गया था गुरुओं की भूमि को नमन करने का अवसर मिला। आज उसके बाद सीधा कुरुक्षेत्र की नगरी लाडवा में आप लोगों के बीच लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व में आया हूं। हरियाणा प्रदेश वासियों को बधाई हरियाणा प्रदेशों हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए यह पर्व बड़ा ही खुशहाली का प्रतीक पर्व है और सभी के जीवन में खुशहाली हो ऐसी मेरी कामना है। इस मौके पर सीएम सैनी के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, शाहाबाद से चुनाव लड़ चुके सुभाष कलसाना भी मौजूद रहे। वहीं अग्नि के अंदर मूंगफली और रेवाड़ी खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों सेअग्नि में अर्पित की और खुद मुख्यमंत्री प्रसाद के तौर पर मूंगफली रेवड़ी का प्रसाद खाते हुए नजर आए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ लाड़वा और प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी।

अखिलेश बोले- केंद्र और राय की मतदाता सूची में अंतर से खुली सरकारों की पोल, वोट की हो रही खुलेआम लूट

लखनऊ।

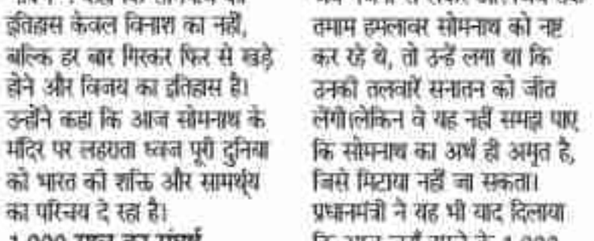

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कराया, जबकि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर राय चुनाव आयोग द्वारा कराया गया। उन्होंने पूछा है कि जब दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते तो फिर कौन सा एसआईआर सही है।

दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते: अखिलेश

रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दोनों ही एसआईआर प्रक्रिया में हर जगह एक ही बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) लगाए गए, इसके बावजूद दोनों के आंकड़ों में बड़ा विरोधाभास सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 2.89 करोड़ कम होकर 12.56 करोड़ रह गई, जबकि पंचायत एसआईआर के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़कर 12.69 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि ये दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते।

सपा प्रमुख ने की ये मांग

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा कि दोनों में कौन सा एसआईआर सही है और अगर एक ही प्रदेश में एक ही बीएलओ के जरिए किए गए एसआईआर में इतने विरोधाभासी आंकड़े सामने आ रहे हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और वोटर लिस्ट के नाम पर मताधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव में आप वोट लूट का एक्रेशन इक्वल करना भूल गए और आपकी पोल पूरी तरह से खुल गई। उन्होंने मांग की कि एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और चुनाव आयोग तुरंत इस विरोधाभास पर स्थिति स्पष्ट करे, ताकि लोकतंत्र की निष्पक्षता और जनता के वोट के अधिकार की रक्षा हो सके।

अमित शाह का केरल में मिशन 2026 का शंखनाद, बोले-

एलडीएफ-यूडीएफ का खेल अब खत्म होगा

केरल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरल में स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का लक्ष्य साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी का सफर आसान नहीं था, लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी ने आज एक मजबूत पहचान बनाई है।

शाह ने स्पष्ट किया कि बीजेपी का अंतिम लक्ष्य केवल जीत नहीं, बल्कि केरल में अपनी सरकार बनाना और भाजपा का मुख्यमंत्री लाना है। शाह ने केरल की मौजूदा राजनीति पर हमला बोलते हुए कहा कि राय इस वक्त एलडीएफ और यूडीएफ की मिलीभगत के कारण ठहराव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों ने बारी-बारी से सत्ता में आकर भ्रष्टाचार करने का गुप्त समझौता कर लिया है। उनके अनुसार, केरल का भविष्य इन दोनों के साथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे राज्य की परंपराओं और विकास की रक्षा करने में विफल रहे हैं। अमित शाह ने पार्टी की बढ़ती ताकत के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 11फीसदी था, जो 2019 में 16फीसदी और 2024 में बढ़कर 20फीसदी के पार पहुंच गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिस तरह पार्टी ने दो सीटों से शुरू करके केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई और असम जैसे राज्यों में जीत हासिल की, वही इतिहास केरल में भी दोहराया जाएगा। गृह मंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल वोटबैंक की राजनीति के कारण PFI और SDPI जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी ही केरल को ऐसी राष्ट्रविरोधी ताकतों से बचा सकती है। शाह ने तीन तलाक कानून का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने तुष्टीकरण की नीति के तहत इसका विरोध किया, जबकि बीजेपी सभी के लिए न्याय, किसी का तुष्टीकरण नहीं के सिद्धांत पर चलती है।

चुनाव नतीजों पर बोले तेजस्वी, जनता हारी और सिस्टम जीता

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में बयान जारी करते हुए कहा कि पिछले साल का चुनाव अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और नतीजों को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि हालिया चुनाव में लोकतंत्र में 'जनता' हारी और 'सिस्टम' जीता। उनके अनुसार जनता पर आधारित लोकतंत्र को धन-तंत्र और मशीन तंत्र में बदल दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें पता है कि किस तरह की साजिश रची गई थी और चुनाव में धोखे व कथित फ्रॉड के जरिए जीत हासिल की गई। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार कैसे बनी, यह सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार के गठन के बाद पहले 100 दिनों के दौरान उसकी नीतियों और फैसलों पर वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह समय सरकार को काम करने और अपने इरादों को दिखाने का है, इसलिए वे इस अवधि में संयम बरतेंगे। राजद नेता ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणापत्र में कई बड़े वादे किए थे, जिनमें माताओं और बहनों को लाभ देने और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात शामिल है। उन्होंने कहा कि अब यह देखना होगा कि इन वादों का क्या होता है और इन्हें जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि वे पहले 100 दिनों तक कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार के कामकाज का आकलन जनता के सामने रखा जाएगा।